[2025] 4 एससीआर 1976: 2025 आईएनएससी 594

एस.डी. जयप्रकाश और अन्य। आदि।

बनाम

भारत संघ और अन्य।

(सिविल अपील संख्या (एस) 5671-5672/2025)

29 अप्रैल 2025

[पामिडीघंटम श्री नरसिम्हा* और जॉयमाल्या बागची, जे.जे.]

विचारणीय मुद्दा

क्या 2015 में अपीलकर्ताओं के नियमितीकरण से पहले प्रदान की गई संविदात्मक सेवा को आर.17, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार उनके पेंशन लाभों के भुगतान में गिना जाना चाहिए।

शीर्ष टिप्पणियां

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम**, 1972 - r-17, 2(g) -** अनुबंध पर सेवा की गणना - अपीलकर्ता शुरू में अनुबंध के आधार पर नियुक्त और बाद में नियमित - नियमितीकरण से पहले संविदात्मक सेवा की अवधि**,** यदि पेंशन के अनुदान के लिए गिना जाना है:

अभिनिर्धारित: हाँ - r.17 पेंशन देने के उद्देश्य से अनुबंध पर सेवा की गिनती से संबंधित है - शीला देवी में r.17 की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने माना कि यद्यपि r.2(g) संविदात्मक कर्मचारियों को उनके आवेदन से बाहर करता है, r.17 एक बार लागू होता है जब इस तरह के संविदात्मक कर्मचारी को बाद की तारीख में नियमित किया जाता है - इस प्रकार, नियमितीकरण पर, पेंशन नियम लागू हो जाते हैं और r.17 के लिए आवश्यक है कि पेंशन की गणना के लिए एक संविदात्मक कर्मचारी के रूप में पिछली सेवा को ध्यान में रखा जाना चाहिए - इसलिए, 2015 में अपीलकर्ताओं के नियमितीकरण से पहले प्रदान की गई संविदात्मक सेवा अवधि को r.17 के अनुसार उनके पेंशन लाभों के भुगतान में गिना जाना चाहिए। [पैरा 7-9]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम शीला देवी, **2023** एससीसी ऑनलाइन एससी **1272 -** पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972

---

*रचयिता

प्रमुख शब्दों की सूची

संविदात्मक कर्मचारी; नियमितीकरण; पेंशन के लिए गिना जाने वाला संविदात्मक सेवा की अवधि; नियमितीकरण से पहले संविदात्मक सेवा अवधि; पेंशन लाभों का भुगतान; परिणामी लाभ; वरिष्ठता, सेवा लाभ; पेंशन; डाटा एंट्री ऑपरेटर; 1996 और 1999 के बीच अस्थायी और संविदात्मक आधार पर 'डेटा प्रोसेसिंग सुविधाओं का युक्तिकरण' नामक कार्य योजना; डाटा एंट्री ऑपरेटर; पेंशन प्रदान करना।

मामले की उत्पत्ति

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या (एस)। 5671-5672/2025

कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु के 23.03.2021 के निर्णय और आदेश से डब्ल्यूपी संख्या 4712 और 4714/2016 में

अधिवक्तागण

अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता:
एम.सी. ढींगरा, वरिष्ट अधिवक्ता,सी.बी. गुरुराज, प्रकाश रंजन नायक, अनिमेश दुबे, गौरव ढींगरा, शशांक सिंह, सुरेंद्र गौतम, ललित नागर

उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता:
के।एम। नटराज, ए।एस।जी।, वत्सल जोशी, शरथ नंबियार, मोहम्मद अखिल, राघव शर्मा, प्रशांत रावत, कृतज्ञ कैट, सुश्री. कृतज्ञ कैट, डीआर। एन। विसाकामूर्ति, गुरमीत सिंह मक्कर।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

<u>निर्णय</u>

पामिडीघंटम श्री नरसिम्हा, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गयी गई।

2. ये अपीलें कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 23.03.2021[1] के आदेश से उत्पन्न होती हैं, जिसमें यह माना गया था कि अपीलकर्ता, जिन्हें शुरू में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था और बाद में नियमित किया गया था, वे अपनी संविदात्मक सेवा की अवधि के लिए वरिष्ठता, सेवा लाभ और पेंशन के हकदार नहीं होंगे। प्रासंगिक नियमों हिमांचल प्रदेश राज्य बनाम शीला देवी[2] में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करने पर हम वर्तमान अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकृति दिए हैं

[1] डब्ल्यूपी नंबर 4712/2016 (एस-कैट) सी/डब्ल्यू डब्ल्यूपी नंबर 4714/2016 (एस-कैट) में।
[2] 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1272।

और उत्तरदाता, यानी भारत संघ को कानून के अनुसार अपीलकर्ताओं को पेंशन लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया।

3. आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलकर्ताओं को 1996 और 1999 के बीच अस्थायी और संविदात्मक आधार पर 'डेटा प्रोसेसिंग सुविधाओं का युक्तिकरण' नामक कार्य योजना के तहत डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण3 दिनांक 01.04.2013[4] के एक आदेश के अनुसार, उत्तरदाताओं ने अपीलकर्ताओं की सेवा को संभावित तिथि से नियमित करने के लिए दिनांक 05.01.2015 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया,

अर्थात, इस आदेश के जारी होने की तारीख से। तदनुसार, अपीलकर्ताओं को दिनांक 01.04.2015 के आदेश द्वारा नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था, जो 05.01.2015 से प्रभावी था। अपीलकर्ताओं ने कैट के समक्ष एक मूल आवेदन को प्राथमिकता दी, जिसमें प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से या कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने की तारीख से अपनी सेवाओं को नियमित करने और उनके वेतन की रक्षा करने और संविदात्मक सेवा की अवधि की गणना करके वरिष्ठता, सेवा लाभ और पेंशन प्रदान करने की प्रार्थना थी। कैट ने दिनांक 19.01.2016 के आदेश द्वारा इसकी अनुमति दी और निम्नानुसार निर्देश दिया:

"31. इसलिए, मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, हम निम्नानुसार आदेश देते हैं:

1. *01/04/2015 को नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति से पहले आवेदकों द्वारा आहरित वेतन और अन्य भत्तों की रक्षा की जाएगी और उन्हें 1.4.2015 को उनके मूल वेतन के रूप में उनके नियमितीकरण से ठीक पहले उनके द्वारा आहरित वेतन की अनुमति दी जाएगी। उनकी वार्षिक वृद्धि तदनुसार निर्धारित की जाएगी।*

2. *जिन आवेदकों के वेतन, जीपीएफ और अनुबंध के आधार पर उनकी नियुक्ति की तारीख से किए गए अन्य योगदान से वे पुरानी पेंशन योजना के तहत आने के हकदार होंगे और अनुबंध के आधार पर प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से सेवा की पूरी अवधि को पेंशन लाभ के रूप में गिना जाएगा।*

3. *वरिष्ठता, एसीपी और अन्य सेवा लाभ आदि के प्रयोजन के लिए, आवेदकों की नियमित सेवा की गणना अनुबंध के आधार पर उनकी प्रारंभिक नियुक्तियों से 10 साल की सेवा पूरी होने की तारीख से की जाएगी।*

[3] इसके बाद "कैट"।

[4] ओ.ए. संख्या 339/2011 में कैट, बैंगलोर, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 57381/2013 (एस-कैट) और संबंधित मामलों को दिनांक 22.04.2014 के आदेश द्वारा बरकरार रखा।

> *32. उत्तरदाता को निर्देश दिया जाता है कि वे आवेदकों का वेतन तय करें और इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो (2) महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त निर्देश के अनुसार परिणामी लाभ प्रदान करें।*"

4. *उत्तरदाता* ने एक रिट याचिका के माध्यम से उपरोक्त आदेश को चुनौती दी, जिसे आंशिक रूप से आक्षेपित आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय ने वरिष्ठता, सेवा लाभ और पेंशन प्रदान करने के लिए संविदात्मक सेवा की अवधि की गणना करने की सीमा तक कैट के निर्देशों को इस आधार पर रद्द कर दिया कि प्रारंभिक नियुक्ति अनुबंध के आधार पर थी और कर्मचारी चयन आयोग की सिफारिश के अनुसार नहीं थी। यह माना गया कि अपीलकर्ता केवल 01.04.2015 से नियमितीकरण और इसके परिणामी लाभों के हकदार होंगे। हालांकि, न्यायालय ने वेतनमान तय करते समय वेतन के संरक्षण के संबंध में कैट के निर्देश को बरकरार रखा।

5. हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एमसी ढींगरा को सुना है। उन्होंने *शीला देवी* (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972[5] के नियम 17 के अनुसार,

अपीलकर्ता संविदात्मक सेवा की अवधि को शामिल करके पेंशन लाभ के हकदार होंगे। दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री वत्सल जोशी ने शीला *देवी* (सुप्रा) को केवल इस आधार पर अलग करने की मांग की है कि इस मामले में प्रारंभिक नियुक्ति स्वीकृत पदों के खिलाफ नहीं थी।

6. हमारा विश्लेषण शुरू करने से पहले, कैट और उच्च न्यायालय के समक्ष और इस न्यायालय के समक्ष की गई प्रार्थनाओं के दायरे पर ध्यान देना आवश्यक है। कैट के समक्ष अनुरोध है कि संविदात्मक सेवा की अवधि की गणना करके पूर्वव्यापी प्रभाव से नियमितीकरण, वेतन की सुरक्षा और वरिष्ठता और सेवा और पेंशन लाभ प्रदान किए जाएं। उच्च न्यायालय के दिनांक 23.03.2021 के आक्षेपित आदेश के अनुसार, केवल अपीलकर्ताओं के वेतन की रक्षा की गई है, जबकि अनुबंध अवधि को शामिल करके वरिष्ठता, सेवा और पेंशन लाभ के लिए उनकी प्रार्थनाओं को खारिज कर दिया गया है। इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतियाँ संविदात्मक अवधि को शामिल करके पेंशन लाभ प्रदान करने तक सीमित हैं,

---

5 इसके बाद "पेंशन नियम"।

शीला देवी (सुप्रा) *में निर्णय पर निर्भरता*। संविदात्मक अवधि के दौरान भूतलक्षी नियमितीकरण, वरिष्ठता और सेवा लाभ प्रदान करने से संबंधित

मुद्दों पर हमारे समक्ष बहस नहीं की गई है। इसलिए हम खुद को पेंशन के मुद्दे तक ही सीमित कर रहे हैं।

7. पेंशन नियमों का नियम 17 पेंशन देने के उद्देश्य से अनुबंध पर सेवा की गणना से संबंधित है, जो वर्तमान मामले में इस मुद्दे को पूरी तरह से कवर करता है। इसे तैयार संदर्भ के लिए नीचे निकाला गया है:

"***17. अनुबंध पर सेवा की गिनती -***

(1)एक व्यक्ति जो शुरू में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक अनुबंध पर सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है और बाद में कर्तव्य में व्यवधान के बिना पेंशन योग्य प्रतिष्ठान में एक मूल क्षमता में उसी या किसी अन्य पद पर नियुक्त किया जाता है, या तो विकल्प चुन सकता है: -

(अ)अंशदायी भविष्य निधि में उस सेवा के लिए किसी अन्य मुआवजे सहित ब्याज सहित सरकारी अंशदान को बनाए रखना; या

(ब)खंड (क) में निर्दिष्ट मौद्रिक लाभों को सरकार को वापस करने के लिए सहमत होना या यदि उन्हें भुगतान नहीं किया गया है तो उन्हें छोड़ देना और उसके बदले में उस सेवा की गणना करना जिसके लिए उपरोक्त मौद्रिक लाभ देय हो सकते हैं।

(2)उप-नियम (1) के तहत विकल्प पेंशन योग्य सेवा में स्थायी अंतरण के आदेश के जारी होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर लेखा अधिकारी को सूचित करते हुए कार्यालय के प्रमुख को सूचित किया जाएगा, या यदि सरकारी कर्मचारी छुट्टी से लौटने के तीन महीने के भीतर उस दिन छुट्टी पर है, जो भी बाद में हो।

(3) यदि उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्यालय प्रमुख द्वारा कोई संचार प्राप्त नहीं होता है, तो सरकारी कर्मचारी को यह माना जाएगा कि उसने संविदा पर प्रदान की गई सेवा के कारण देय या भुगतान किए

गए मौद्रिक लाभों को प्रतिधारण करने का विकल्प चुना है।"

8. यह नियम शीला देवी (सुप्रा) *में विचार और व्याख्या के लिए गिर गया,* जहां इस न्यायालय ने माना कि हालांकि पेंशन नियमों के नियम 2 (जी) में संविदात्मक कर्मचारियों को उनके आवेदन से बाहर रखा गया है, नियम 17 बाद की तारीख में ऐसे संविदा कर्मचारी को नियमित करने के बाद लागू होता है। इसका प्रभाव यह है कि नियमितीकरण पर, पेंशन नियम लागू हो जाते हैं और नियम 17 के लिए आवश्यक है कि पेंशन की गणना के लिए एक संविदात्मक कर्मचारी के रूप में पिछली सेवा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।[6] इस आलोक में, और इस बात पर विचार करते हुए कि नियम 17 में नियमित कर्मचारी को अंशदायी भविष्य निधि में सरकार के अंशदान को बनाए रखने या ऐसी राशि वापस करने या उसे छोड़ने के विकल्प का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है यदि उन्हें उस सेवा अवधि की गणना के बदले में भुगतान नहीं किया गया है जिसके लिए ऐसे लाभ देय हो सकते हैं, *शीला देवी* (सुप्रा) में इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

"11. उपरोक्त तर्क को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि अपील में कोई योग्यता नहीं है, हालांकि, निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं: -

(१) राज्य संबंधित सभी कर्मचारियों (जिन्हें संविदात्मक रोजगार के बाद

नियमित किया गया था) द्वारा विकल्प का प्रयोग करने के तरीके और तरीके को इंगित करने के लिए तत्काल कदम उठाएगा, भले ही वे किसी भी तारीख को या वर्ष 2003 से पहले या बाद में, एक समय सीमा के भीतर, आज से आठ सप्ताह के भीतर।

(२) नोटिस में बताए गए समय के भीतर विकल्प प्राप्त करने के बाद, संबंधित कर्मचारी (कर्मचारी) जो प्रासंगिक विकल्पों का प्रयोग करते हैं, उन्हें उन राशियों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए जो उन्हें योगदान के लिए किसी भी राशि की आवश्यकता होने पर स्पष्ट रूप से भेजनी होगी।

---

[6] *शीला देवी* (सुप्रा), पैरा 9.

(३) विकल्पों को संसाधित किया जाना चाहिए और विकल्प प्राप्त करने की अंतिम तिथि से आठ सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

(४) भुगतान के लिए समय सीमा भी इंगित की जानी चाहिए और पूरी प्रक्रिया चार महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और पेंशन या पारिवारिक पेंशन तय करने वाले सभी आदेश जारी किए जाएंगे।"

9. पेंशन नियमों के नियम 17 की स्पष्ट भाषा के साथ-साथ *शीला देवी* (सुप्रा) में इसकी व्याख्या के आलोक में, 2015 में अपीलकर्ताओं के नियमितीकरण से पहले प्रदान की गई संविदात्मक सेवा अवधि को नियम 17 में निर्धारित तंत्र के अनुसार उनके पेंशन लाभों के भुगतान के लिए गिना जाना चाहिए। यहां ऊपर निकाले गए शीला *देवी* (सुप्रा) में जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप, हम प्रतिवादी भारत संघ को तत्काल कदम उठाने और अपीलकर्ताओं के लिए पेंशन नियमों के नियम 17 के तहत प्रदान किए गए विकल्प का प्रयोग करने के तरीके और तरीके को इंगित करने के साथ-साथ उन राशियों को सूचित करने का निर्देश देते हैं जो अपीलकर्ताओं को नियमों

के तहत पेंशन देने का विकल्प चुनने की स्थिति में भेजी जाएंगी।

10. उपरोक्त तर्क और निर्देशों के साथ, हम आंशिक रूप से एसएलपी (सी) संख्या 19539-19540/2021 से उत्पन्न होने वाली वर्तमान अपीलों की अनुमति देते हैं और डब्ल्यूपी संख्या 4712/2016 (एस-कैट) सी/डब्ल्यू डब्ल्यूपी संख्या 4714/2016 (एस-कैट) में उच्च न्यायालय के 23.03.2021 के आक्षेपित आदेश को रद्द करते हैं

11.के रूप में कोई आदेश नहीं।

12. अपीलकर्ता संख्या 21 के अभिलेख एलआर को अभिलेख पर लाने के लिए आईए डायरी संख्या 44115/2025 की अनुमति है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया गया है।

मामले का परिणाम: अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

शीर्ष टिप्पणियां : दिव्या पाण्डेय द्वारा तैयार की गयी

<u>यह अनुवाद शिव बचन यादव, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।</u>